



हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू के नेतृत्व में निकाली गई एंटी-चिट्टा वॉकथॉन में शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों सहित हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस वॉकथॉन में भाग ले रहे युवाओं से नशे से दूर रहने और नशा मुक्त हिमाचल के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

आज से हड़ताल पर जाएंगे डॉक्टर

आईजीएमसी प्रकरण में सीएम के दोबारा जांच करने के आश्वासन पर भी नहीं माने

सत्यदेव भारद्वाज, अनंत ज्ञान ब्यूरो

शिमला। हिमाचल में रेजिडेंट डॉक्टरों शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। सीएम सुखविंद सिंह सुक्खू के साथ मीटिंग के बाद शुक्रवार दोपहर बाद रेजिडेंट डॉक्टरों एसोसिएशन(आरडीए), हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। आरडीए की मांग है कि डॉ. राघव निरुला के खिलाफ टर्मिनेशन की कार्रवाई को निरस्त किया जाए। आईजीएमसी शिमला के भीतर भीड़ द्वारा डराने-धमकाने/ट्रायल की गंभीर घटना मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर, डॉ. राघव को जान से मारने की धमकी तथा उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले नरेश दस्ता पर मामला दर्ज किया जाए। इससे पहले सुबह के वक्त ओक ओवर में सीएम सुक्खू के साथ इनकी मीटिंग हुई।



डॉ. निरुला के टर्मिनेशन ऑर्डर निरस्त करने की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश पर डॉक्टरों।

डॉ. राघव निरुला के टर्मिनेशन ऑर्डर निरस्त करने पर अड़े

इस बैठक से कुछ समय के लिए यह उम्मीद जगी थी कि स्थिति सामान्य हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने मामले में दोबारा जांच करने, डॉक्टरों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और समाधान निकालने का भरोसा भी दिया। बावजूद इसके डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया। डॉक्टरों का साफ कहना है

कि जब तक कार्यस्थल पर सुरक्षा, सम्मान और निष्पक्ष कार्रवाई की ठोस गारंटी नहीं मिलती, तब तक केवल आश्वासन के आधार पर काम पर लौटना संभव नहीं है। गौर रहे कि गत 22 दिसंबर को

एम्स दिल्ली के डॉक्टर भी समर्थन में उठते

अब तो एम्स दिल्ली के डॉक्टरों भी आईजीएमसी शिमला के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के समर्थन में उठ आए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है।

आईजीएमसी में हुई मारपीट की घटना का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने तेजी से जांच कर संबंधित डॉक्टर को सेवा से हटा दिया है। इसी फैसले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए आंदोलन का रास्ता अपनाया।

पुलिस अलग से कर रही पूरे प्रकरण की जांच

इस पूरे प्रकरण में मरीज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस अलग से जांच कर रही है। हालांकि अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाया है। पुलिस अब उस व्यक्ति से मूल (ऑरिजनल) वीडियो रिकवर करेगी, जिसने घटना का वीडियो शूट किया था।

डॉक्टरों का कहना है कि न तो पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हुई और न ही दोनों पक्षों को आमने-सामने रखकर उन्हें सुना गया। इसी असंतोष ने पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर दिया है।

शुक्रवार को हजारों डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर रहे। उनके सामूहिक अवकाश पर रहने का सबसे ज्यादा असर आईजीएमसी शिमला समेत प्रदेश के बड़े अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। इससे ओपीडी सेवाएं लगभग पूरी तरह ठप रही। सुबह-सुबह इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचे मरीजों को घंटों इंतजार के बाद बिना उपचार लौटना पड़ा। दूर-दराज के इलाकों से आए मरीज और उनके परिजन अस्पताल परिसरों में मायूस बैठे नजर आए।

सामूहिक अवकाश से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं, मरीज परेशान

कनाडा में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या

एजेंसी, टोरंटो। कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास भारतीय मूल के 20 वर्षीय छात्र शिवांक अवस्थी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह टोरंटो में 2025 की 41वीं हत्या है। यह घटना कैंपस के पास होने से छात्रों में डर का माहौल है और यूनिवर्सिटी ने भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया। पुलिस के अनुसार, 23 दिसंबर को दोपहर में हत्या की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर शिवांक अवस्थी को गोली लगी हालत में पाया और उसे मृत घोषित कर दिया। (अनंत ज्ञान)

अंदर के पन्नों पर पढ़ें

- ▶ **प्रदेशभर में 108 और 102 एंजुलेस कर्मियों का प्रदर्शन** - पृष्ठ 3
- ▶ **कृषि विज्ञान केंद्र मंडी को मिला सर्वश्रेष्ठ केवीके पुरस्कार** - पृष्ठ 4
- ▶ **चिट्टे से जंग के लिए बिलासपुर भी हुआ तैयार, अग्र जन सैनिक** - पृष्ठ 6
- ▶ **खड़बू में गिरने से बची एचआरटीसी की बस** - पृष्ठ 9
- ▶ **कर्मियों ने न्यूट्राम केन, ओवरस्ट्रक के खिलाफ जताया रोष** - पृष्ठ 12

भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो : मद्रास हाईकोर्ट

एजेंसी, चेन्नई

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी 16 साल से कम उम्र वालों के लिए

ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करने का दिया सुझाव

सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने कहा कि इसपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। मदुरै बेंच की डीविजन बेंच जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस केके रामकृष्णन ने यह बात नाबालिगों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट आसानी से मिल जाने के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। याचिकाकर्ता एस विजयकुमार के वकील केपीएस पलानीवेल राजन ने ऑस्ट्रेलिया के नए कानून का हवाला दिया था।

कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर और सख्त नियम लागू किए जाएं। उन्हें अनिवार्य रूप

ऑस्ट्रेलिया मॉडल?

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने नवंबर 2024 में 'ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट बिल' पास किया था। इस कानून का मकसद बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक कंटेंट और साइबर ज़ोरखियों से बचाना है। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया-एक्स (ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नेपचैट, यूट्यूब जैसी बड़ी सोशल मीडिया साइटों से दूर रखने का प्रवधान है।

से पैरेंटल विंडो सर्विस (पैरेंटल कंट्रोल) देने के लिए कहा जाए, जिससे माता-पिता अपने बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी को फिल्टर और कंट्रोल कर सकें। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने 9 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। (अनंत ज्ञान)

राखिल काहलौं बनीं एचपीपीएससी की सदस्य

अभी जलशक्ति विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत, ज्वाइनिंग से पहले देंगी इस्तीफा

अनंत ज्ञान ब्यूरो, शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राखिल काहलौं को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) का सदस्य नियुक्त किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्यपाल की स्वीकृति के साथ ही यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। एचपीपीएससी में

सदस्य के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्हें आईएएस सेवा से औपचारिक रूप से इस्तीफा देना होगा। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब उनकी नियमित सेवानिवृत्ति जनवरी 2026 में प्रस्तावित थी। वर्तमान में राखिल काहलौं राज्य सरकार में जलशक्ति विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत



हैं। वह वर्ष 2008 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और राज्य प्रशासन में उनकी गिनती वरिष्ठ अधिकारियों में होती है। एचपीपीएससी में उनकी तैनाती छह वर्षों के लिए की गई है। लोक सेवा आयोग राज्य में मुख्य रूप से राजपत्रित पदों और कुछ अराजपत्रित पदों के लिए चयन परीक्षाएं आयोजित करता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा-भारत रत्न और पद्म अवॉर्ड कोई उपाधि नहीं

एजेंसी, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान कोई उपाधि (टाइटल) नहीं हैं। ऐसे में इन्हें किसी के नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट ने यह बात शुक्रवार को एक याचिका के केस टाइटल में पद्म श्री लिखे जाने पर कही। दरअसल, जस्टिस सोमेश्वर सुंदरेसन की बेंच याचिका की सुनवाई कर रही थी। इसमें 2004 में पद्म श्री से सम्मानित डॉ. शरद मोरेस्वर हाईकोर्ट भी एक पक्षकार थे। केस टाइटल में उनका नाम पद्म श्री डॉ. शरद मोरेस्वर हाईकोर्ट लिखा गया था। इस पर जज ने आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि कानून के अनुसार ऐसा करना गलत है। (अनंत ज्ञान)

केरल में पहली बार भाजपा का मेयर

एजेंसी, तिरुवनंतपुरम। केरल में पहली बार भाजपा का मेयर चुना गया है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शुक्रवार को हुए मेयर चुनाव में भाजपा के वीवी राजेश को 51 वोट मिले, जिसमें एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन भी शामिल था। वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के पी. शिवाजी को 29 वोट, जबकि कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार केएस सवरिताथन को 19 वोट मिले, जिनमें से दो को बाद में अमान्य घोषित कर दिया गया। दरअसल 9 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों का रिजल्ट आया था। 50 वार्डों पर भाजपा जीती थी। पिछले 45 साल से यहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा का कब्जा था। केरल के 1,199 स्थानीय निकायों के लिए दो फेज 9 और 11 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। इनमें 6 कॉर्पोरेशन, 86 नगर पालिकाएं, 14 डिस्ट्रिक्ट काउंसिलें, 152 ब्लॉक पंचायत और 941 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। (अनंत ज्ञान)

पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के लिए खतरा : पुतिन

एजेंसी, नई दिल्ली

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 24 साल पूर्व 2001 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से अपनी पहली मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को लेकर चिंता जताई थी। पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान असल में एक सैन्य शासन यानी जुंटा है, जिसके पास परमाणु हथियार हैं। यह कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है। पुतिन के मुताबिक, इसके बावजूद पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते, जो चिंता की बात है। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

दोनों नेता पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, राजनीतिक अस्थिरता और परमाणु कमांड सिस्टम को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर हालात बिगड़े तो परमाणु तकनीक गलत हाथों में जा सकती है। यह जानकारी दोनों के बीच 2001 से 2008 के दौरान हुई बातचीत के



रूसी राष्ट्रपति ने 24 साल पहले जॉर्ज बुश को किया था आगाह

डीक्लासिफाइड दस्तावेज सामने आए हैं। ये दस्तावेज अमेरिका की नेशनल इन्फार्मेशन आर्काइव ने सूचना के अधिकार कानून के तहत जारी किए हैं। यह बातचीत ऐसे समय में हुई थी जब दुनिया में आतंकवाद और दक्षिण एशिया की सुरक्षा को लेकर हालात काफी संवेदनशील थे। पुतिन का मानना था कि किसी गैर-लोकतांत्रिक देश का परमाणु हथियारों से लैस होना वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। 2001-2008 के दौर में पाकिस्तान में सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ का शासन था। (अनंत ज्ञान)

क्रिकेटर वैभव समेत 20 बच्चों को बाल पुरस्कार

राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, 2 बच्चों को मरणोपरांत मिला

एजेंसी, नई दिल्ली

वीर बाल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को 20 बच्चों को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया। इन बच्चों को 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। 14 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली में हैं, इसलिए वे आज विजय हजारे ट्रॉफी में मणिपुर के खिलाफ मैच नहीं खेल रहे हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बॉर्डर पर जवानों को चाय-नाश्ता देने वाले फिरोजपुर के श्रवण सिंह भी शामिल हैं। 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। इनमें

तमिलनाडु की ब्योमा और बिहार के कमलेश कुमार का नाम शामिल है। इनके पुरस्कार माता-पिता ने लिए। पीएम मोदी ने विजेता बच्चों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और कहा कि जेन जी और जेन अल्फा ही हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। (अनंत ज्ञान)

जेन जी हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे : पीएम

पीएम मोदी ने कहा कि यहां मेरा युवा भारत है। संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां एकत्रित हैं। एक तरह से आप सभी जेन जी हैं। जेल अल्फा भी हैं। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। मैं जेन-जी की योग्यता और आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं। इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। हमारे यहां कहा गया है- 'बालादपि ग्रहीतव्यं विद्या युक्तमुक्तं मनीषिभिः' अमृतं विषसंयुक्तं यदुक्तं तदपि त्यजेत्', अर्थात्, अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमान की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए।

चिंतनीय डॉक्टर बोले-वायु प्रदूषण से बढ़ीं दिल की बीमारियां; हल ढूंढने में काफी देर हो चुकी

कोविड के बाद प्रदूषण भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट

एजेंसी, नई दिल्ली

भारत में वायु प्रदूषण कोविड-19 महामारी के बाद सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बन चुका है। ब्रिटेन में काम करने वाले भारत के कई सैनिक डॉक्टरों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में यह दावा किया है।

डॉक्टरों ने कहा कि आने वाले सालों में प्रदूषण से लोगों की सेहत और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर लंबे समय तक असर पड़ेगा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर तत्काल और ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह समस्या हर साल और गंभीर होती जाएगी। डॉक्टरों ने कहा कि पिछले 10 सालों में हृदय रोगों में बढ़ोतरी को अक्सर मोटापे से



जोड़ा गया, लेकिन इसमें कारों और विमानों से निकलने वाले जहरीले तत्वों की बड़ी भूमिका है।

डॉक्टरों के मुताबिक, दिसंबर में दिल्ली के अस्पतालों में सांस संबंधी मरीजों की संख्या में 20 से 30% की बढ़ोतरी देखी गई। इनमें कई युवा और पहली बार इलाज कराने वाले मरीज शामिल थे। लंदन

वर्तमान में जो इलाज हो रहा, वह काफी नहीं

इंग्लैंड स्थित लिवरपूल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट (फेफड़ों के डॉक्टर) मनीष गौतम ने कहा कि वायु प्रदूषण पर सरकार का नया फोकस जरूरी है, लेकिन इसमें काफी देरी हो चुकी है। गौतम के पास यूके की नेशनल हेल्थ में 20 सालों से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम पहले से मौजूद हैं, लेकिन वे अब इस रोक पाने के लिए अपने आप में काफी नहीं हैं। उत्तर भारत में रहने वाले लाखों लोगों में नुकसान पहले ही हो चुका है। जो इलाज हो रहा है, वह समस्या का केवल एक छेदा हिस्सा है। (अनंत ज्ञान)

2022 में भारत में प्रदूषण से 17 लाख लोगों की मौत

'लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025' रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में भारत में 2.5 पीएम प्रदूषण से 17 लाख से ज्यादा मौतें हुईं। इनमें से 2.69 लाख मौतें सड़क परिवहन में पेट्रोल के इस्तेमाल से जुड़ी थीं। मई में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की एक वैश्विक स्टडी में कहा गया कि गाड़ियों से निकलने वाली जहरीली गैसों को कंट्रोल करने वाली नीतियां 2040 तक दुनियाभर में 19 लाख जानें बचा सकती हैं और बच्चों में अस्थमा के 14 लाख नए मामलों को रोक सकती हैं।

